

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 1965 (कार्तिक 8, 1887)

No. 441

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 1965 (KARTIKA 8, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## नोटिस

## NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपन्न 15 अक्तूबर 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 15th October 1965 :—

| अंक<br>(Issue<br>No.) | संख्या और तारीख<br>(No. and Date)         | द्वारा <b>जारी किया ग</b> या<br>(Issu <b>e</b> d by) | विषय<br>(Subject)  |
|-----------------------|---|--|--|
|                       | कम्पनी-3(12)/65,<br>इनांक 12 अक्तूबर 1965 | इस्पात और<br>खान मंत्रालय                            | मुख्य लागत लेखा । अधिकारी श्रो० एन० कृष्णन को<br>इस्पात की उत्पादन लागत को जांच समिति का<br>सदस्य नियुक्त करना । |
|                       | 12-ETC(PN)/65,<br>ated 15th October 1965  | Min. of Commerce.                                    | Export of De-oiled groundnus cake (extractions).   |

उपर लिखे असाधारण राजपत्नों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिवित लग्डन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्न भेजने पर भेज दी जाएगी । मांग-एत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्नों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भोतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indust to the Manager of Publications, Civil Lines, Delbi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of Issue of these Gazettes.

## विषय-सूची (CONTENTS)

|  | पृष्ठ   | वृष्ट     |
|--|---|-----------|
|  | (fages)   | (Pages)   |
| भाग I —खंड 1 — (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 591 भाग I —खंड 2 — (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत | भाग 1—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं  प्रान 1—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, प्दोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं | 53<br>553 |
| सरकार के मंत्रालयों तथा उज्ज्वतम न्यायालय<br>द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की<br>नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से<br>संबंधित अधिसूचनाएं 907  | भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और<br>विनियम<br>भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी   |           |

|  | ্            |  | पृष्ठ        |
|--|--------------|--|--------------|
|  | (Pages)      |  | (Pages)      |
| भाग II—खंड 3—उप- <b>खं</b> ड (i)—(रक्षा मंत्रालय<br>को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और<br>(संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर)   |              | भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा<br>जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें   | 389          |
| केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए<br>विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये  |              | भाग III— <b>खंड 3मुख्य आयुक्</b> तों द्वारा या उनके<br>प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं  | 113          |
| साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेण, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)   | 1617         | भाग III—श्वंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की<br>गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं,<br>आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं  | 2745         |
| भाग 11 - खड 3 - उप खड (ii) - (रक्षा मंत्रालय<br>को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और<br>(संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर)<br>केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत<br>बनागे और जारी किये गये आदेश और अधि- |              | भाग IVगैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी<br>संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें  | 207          |
| सूचनाएं  | <b>3</b> 521 | पूरक सं० 4.1   |              |
| भाग II — खंड 4 — रक्षा मझालय द्वार। अधिसृचित<br>विधियः नियम और आदेश  | 265          | 23 अक्तूबर 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी माप्ताहिक रिपोट   | 1517         |
| भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-<br>सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों<br>और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन  |              | 2 अक्तूबर 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह के<br>दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक<br>आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी   |              |
| कार्यालयों द्वारा जारी की गई श्रिधिसृचनाएं   | 713          | बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकडे   | 1527         |
| PART I—Section 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India tother than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court    | 591          | PART II—Section 3.—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Min- istries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Cen- tral Authorities (other than the Adminis- trations of Union Territories) | 3521         |
| PART I.—Section 2.—Notifications regarding   | 391          | PART II—Section 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence  | 263          |
| Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court  | 907          | PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of  |              |
| PART I—Section 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the  |              | India  | 713          |
| Ministry of Defence  | 53           | issued by the Patent Office, Calcutta  | <b>3</b> 89  |
| PART I - Section 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of   |              | PART III—Section 3Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners  | 113          |
| PART II —Section 1.—Acts, Ordinances and,  | 553          | PART III—Section 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies   | <b>2</b> 745 |
| Regulations  | ~            | PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies   | <b>2</b> .43 |
| Committees on Bills  | _            | Supplement No. 44—   |              |
| PART II Section 3.—Sub-Section (i)—Geogral Statutory Rules (including orders, byelaws, etc. of a general character) issued by  |              | Weekly Epidemiological Reports for week-ending 23rd October 1965   | 1517         |
| the Ministries of the Government of India other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)   | 1617         | Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 2nd October 1965   | 1527         |

## भाग I-- खण्ड 1

## PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा आरी की गई विद्यीतर निथमों, विनियमों तथा आवेडोॉ और संकल्पों से संबंधित अधिसुचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

## वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1965

सं० 12/4/65-ई० प्रा०—भारत रक्षा नियम 1962 के नियम 133-वी के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा यह आदेश देती है कि पाकिस्तान इण्टरनेशनल एयरलाइन्स कारपीरेशन की भारत में जितनी चल अथवा अचल सम्पत्ति है अथवा उसके पास है अथवा उसकी ओर से व्यवस्थित है वह अब भारत के शत्नु सम्पत्ति संरक्षक के अधिकार में तत्काल ही चली जायगी।

बी० डी० जयाल, संयुक्त सचिव

# खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्तूबर 1965

सं॰ एफ॰ 10-1/65 फैट—राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन सम्पर्क सिमिति, जो भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (अब खाद्य और कृषि) के प्रस्ताव सं॰ एफ॰ 16-72/47-पालिसी, दिनांक 8 नवम्बर 1948 (अद्यतन मंजीधित) के अनुसार निर्मित हुई थी, में प्रतिनिधित्व करने के लिये लोकसभा के अद्योलिखित सदस्यों को 31 मार्च 1968 तक तीन वर्ष के लिये निर्याचित किया गया है:—

- 1. श्री मनीराम बागडी
- 2. श्री गोपालासामी थैगोंडार
- 3. श्री कृंबर कृष्ण वर्मा
- 4. श्री पुरुषोत्तमदास २० पटेल

जगदीशचन्द्र माथुर, संयुक्त सचिव

## परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1965

#### संस्ताव

#### पत्तन

संख्या 20-पी० जी० (24)/64—परिवहन मंत्रालय के संस्ताय संख्या 20-पी० जी० (24)/64-दिनांक 11 अगस्त, 1964 के आंशिक रूपान्तरण में भारत सरकार ने निश्चय किया है कि मद्रास सरकार के मंत्री (निर्माणकार्य) के स्थान पर मद्रास सरकार के सहकारिता के मंत्री राष्ट्रीय पत्तन मंडल के सदस्य होंगे।

#### आर्च श

आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव की एक प्रति, उक्त मंडल के सदस्यों, राष्ट्रपति के सैनिक तथा निजी सचिवों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, और भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों को प्रेषित कर दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य स्वना के लिये यह संस्ताय भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

एन० पी० माथुर, संयुक्त सचिव

## DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY

New Delhi-1, the 18th October 1965

## RESOLUTION

No. 15/7/65-SCT.II.—The Government of India have decided to extend the term of the present Central Advisory Board for Tribal Welfare reconstituted under the Ministry of Home Affairs Resolution No. 6/5/62-SCT.III(B), dated the 16th May 1964, by one year, that is, up to the 16th August 1966.

## ORDER

CROBRED that the above be published in the Gazette of India.

D. C. DAS, Secy.

## MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 13th October 1965

No. F. 19(10)BC/65.—In view of the difficulties which are being experienced in some of the border areas of the Punjab, as a result of the outbreak of hostilities, the Government of India have decided to provide during a temporary period for the grant of additional credit facilities in the said areas through the existing agencies. In pursuance of this decision, it is hereby notified that the Government of India will be prepared to enter into agreements with scheduled banks which have offices in the districts of Ferozepore, Amritsar, Gurdaspur, Jullundur, Ludhiana and Kapurthala on the following terms and conditions:

- 2. The Central Government's guarantee will be in respect of loans and advances granted to—
  - (i) industrial units other than those in respect of which a guarantee can be applied for under the credit guarantee scheme for small-scale industries, and
  - (ii) establishments or persons carrying on business as the sellers or suppliers of goods.

provided that in either case the industrial unit, establishment or other person as the case may be has complied with the provisions of the Emergency Risks (Factories) Insurance Scheme or the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme, if it is applicable to it or to him. The amount of the Central Government's guarantee will be limited to ten per cent of the market value of the goods or properties pledged, hypothecated or mortgaged to the lending scheduled banks or the actual increase in the amount of the loan or advance over the amount outstanding on the 1st September 1965, whichever is less.

3. The guarantee in pursuance of this notification will be available only in respect of secured loans and advances granted before the 1st March 1966 on the pledge, hypothecation or mortgage of goods and properties. On the 1st March 1966 or before such subsequent date as may be specified by the Central Government in this behalf, the loans or advances in respect of which any guarantee has been furnished by the Central Government shall be called up by the scheduled banks to which the guarantee has been furnished, and fresh loans or advances, not supported by the Central Government's guarantee, may be granted by the banks to the borrowers, if necessary, in new accounts which shall be opened separately for this purpose. The guarantee offered by the Central Government shall, on the loans or advances being called up, cease to be in force, except to the extent of the liabilities incurred or obligations arising out of the guarantees at the time that they are revoked.

- 4. Every scheduled bank shall continue to hold all the promissory notes and unrealised securities even after the reimbursement to it by the Government of any loss in pursuance of the guarantee and shall agree to modify, alter or forego its rights in respect of any securities available to it to such an extent as to permit the Central Government to obtain and hold a pari passu charge on the said securities to the extent of the percentage share of the risks borne by that Government.
- 5. A scheduled bank seeking a guarantee in pursuance of this notification shall, in the event of the Government's guarantee being invoked in the case of any loan or advance, undertake—
  - (i) to credit to the Central Government any sums which may be realised thereafter from the industrial unit, establishment or person to whom the loan or advance has been granted, and
  - (ii) not to grant any other loan or advance to the industrial unit, establishment or person on whose behalf the guarantee has been invoked. after the date on which it has been invoked,

until such time as the amounts due to the Central Government have been paid to, or adjusted in favour of, the Central Government.

6. The Director General Resettlement, Cabinet Secretariat, New Delhi, will be the authority who will enter into the prescribed agreements of guarantee with the scheduled banks eligible for the Central Government's guarantees in pursuance of this notification. All scheduled banks operating in the districts referred to in this notification are advised to contact the officer concerned immediately in case they wish to avail themselves of the facilities provided by the Central Government under this scheme.

R. K. SESHADRI, Director (Banking).

#### MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 13th October 1965

No. 12/4/65-E.Pty.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government hereby orders that all property in India, movable and immovable, belonging to, or held by, or managed on behalf of, the Pakistan International Airlines Corporation shall vest in the Custodian of Enemy Property for India with immediate effect.

B. D. JAYAL, Jt Secy.

## New Delhi, the 18th October 1965

No. F. 29(1)Plant (B)/62.—In continuation of this Ministry's notification of even number, dated the 18th September 1965, it is hereby notified that the Chairman and existing Members of the Cardamon Development and Marketing Advisory Committee will continue to hold office for a further period of two months with effect from the 1st November 1965.

S. BANERJEE, Dy. Secy.

New Delhi, the 19th October 1965

## RESOLUTION

IRON ORE EXPORT (PROJECT) COMMITTEE

No. 15/66/64-M&F.—In further modification of Government of India Resolution No. 15/49/64-M&F, dated the 3rd October 1964, as amended by Resolution of even number, dated the 15th February 1965, the Government of India have decided that in para 3 of the Resolution regarding constitution of this Committee, the following amendment and addition may be made:—

- The name of Shri G. S. Khosla, Director, Traffic (Transportation), Railway Board may be substituted in place of Shri Jagjit Singh, Director (Transportation), Rly, Board.
- (ii) The name of Shri K. L. Luthra, Director, Transport Division, Planning Commission may be added "as member" just above the name of Shri S. K. Mukherjee.

## ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. K. MUKHERJEE, Jt. Secy.

# MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (Department of Agriculture)

New Dellii, the 13th October 1965

#### RESOLUTION

No. F. 6-4, 65-AE.—The Government of India have decided that Shri V. N. Goenka of Village Lakhangava, District Shivpuri (Madhya Pradesh) will also be a member of the Panel of Leading Progressive Agriculturists constituted under this Ministry's Resolution No. F. 6-4/65-3E, dated the 27th May 1965.

#### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered that the Resolution may be communicated to all concerned.

B. SIVARAMAN, Secy.

## New Delhi, the 20th October 1965

No. F. 10-1/65-FAIT.—The following members of the Lok Sabha have been elected to serve as members of the National Food and Agriculture Organisation Liaison Committee in accordance with the late Ministry of Agriculture (Now Food and Agriculture), Resolution No. F. 16-72/47-Policy, dated the 8th November 1948, as amended to date, for a period of three years ending 31st March 1968:—

- 1. Shri Mani Ram Bagri.
- 2. Shri Gopalasami Thengondar,
- 3. Shri Kunwar Krishna Verma.
- 4. Shri Purushottamdas R. Patel,

J. C. MATHUR, Jt. Seey.

# MINISTRY OF TRANSPORT

## (Transport Wing)

New Delhi, the 19th October 1965

## RESOLUTION

#### PORTS

No. 20-PG(24)/64.—In partial modification of the Ministry of Transport Resolution No. 20-PG(24)/64, dated the 11th August 1964, the Government of India have decided that the Minister for Cooperation, Government of Madras, shall be a member of the National Harbour Board vice the Minister (Works), Government of Madras.

## CRDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabiner Secretariat, the Planning Commission, the Ministeres/ Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. P. MATHUR, Jt. Scay.

## MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 12th October 1965

## RESOLUTION

No. DW V.501(4)/64.—Further to this Ministry's Resolution No. DW.V.501(4)/64, da'ed the 28 h June 1965, Government are pleased to extend the period for submission of the Report by the Expert Committee constituted for suggesting a comprehensive plan for controlling floods and inundation in the coastal deltaic areas of Andhra Pradesh, up to end of November 1965.

## ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and copies communicated to all persons concerned.

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the State Government of Andhra Pradesh with the request to them for publishing it in the State Gazette for general information.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India, the Planning Commission, the Prime Minister's Sectt., the Military Secretary to the President, the Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt., Department of Parliamentary Affairs and the Comptroller and Auditor General of India.

P. R. AHUJA, Jt. Secy.